'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

प्रकाशन तिथि– 30 नवंबर, 2014

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 18 ● अंक 1 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 16 से 30 नवंबर, 2014

17वीं महारैली के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

दिनांक : 8 दिसंबर, 2014, प्रात: 10 बजे, स्थान : रामलीला मैदान, नई दिल्ली

साथियो,

आपको ज्ञात हो गया होगा कि फिर से एक बार रिकॉर्ड तोड़ रैली 8 दिसंबर, 2014 को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इरादा है कि 11 दिसंबर, 2000 की रैली से भी आगे निकल जाएं। संख्या बल ही निर्णायक होता है, जो हमने पूर्व में करके दिखा भी दिया है। यह 17वीं रैली है। सभी जानते हैं कि अनुसूचित जाति / जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ गैर राजनैतिक है और सदा रहेगा। हमारे समाज का यह देश का सबसे बड़ा संगठन है और अब इसे और ताकतवर बनाना है। ईर्ष्यावश या अचंभित होकर कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष का सांसद रैली कैसे कर सकता है? जवाब तो दिया गया कि यह पहली नहीं है बल्कि 17वीं है। दूसरी बात है कि सांसद की हैसियत से नहीं बल्कि परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन की हैसियत से रैली कर रहा हूं। नई सरकार है तो कुछ काम करने के लिए समय देना चाहिए, यह हम जानते हैं। यदि हम रैली करने का सिलसिला तोड़ देते हैं तो हमारे कार्यकर्त्ता भटक और टूट जाएंगें और इसका फायदा फर्जी दलित नेताओं और संगठनों को मिल जाएगा। एक मां जो अपने बच्चे से बेहद प्यार करती है, वह भी कई बार बिना रोए दूध नहीं पिलाती, तो इसी बात को मद्देनजर रखकर हम बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं ताकि सरकार को लगे कि हमारी समस्या और शक्ति क्या है? हमारे समाज की ताक़त कर्मचारी-अधिकारी ही हैं और पहली बार पिछली लोक सभा में इसके समर्थन से कितने चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। समर्थन दिया है तो सम्मान और अधिकार लेने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान कहा था कि आने वाला दशक दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों का है और हमें पूरा विश्वास है कि जो कार्य पिछली सरकार ने नहीं किया है, अब हो सकेगा।

साथियों, यह आपकी शक्ति के प्रदर्शन की परीक्षा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री अमित शाह, वरिष्ठ नेता श्री नितिन गडकरी आदि रैली को संबोधित करेगें। कोशिश है कि माननीय प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया जाए। इनको आमंत्रित करने की सूचना सार्वजनिक नहीं की जा रही है, क्योंकि लगेगा कि आपकी ताक़त से नहीं बल्कि इनके आने के प्रचार से रैली सफल हुई। वास्तव में आपकी ताक़त ही काम आएगी। अब आप सोच लें कि जो सरकार की नीतियां बनाते हैं और उनकी उपस्थिति में रैली कमजोर होती है तो कितना इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसलिए छुट्टी लेकर तन-मन-धन से इसे सफल बनाने के लिए जुट जाएं। रेलवे के आर्डर की की कापी www.uditraj.com/rally-2014 से डाउनलोड की जा सकती है। रेलवे विभाग ने अलग से आदेश जारी करवाया है, इसलिए उनसे सम्पर्क करके रैली में भाग लेने में सहयोग लें। बिना धन के इतनी बड़ी रैली कराना संभव नहीं है, इसलिए शीघ्रातिशीघ्र परिसंघ के खाते में सहयोग राशि जमा करवाएं और जमा करने के पश्चात एस.एम.एस. अथवा ईमेल द्वारा सूचित करें –

खाते का विवरण इस प्रकार है :-

All India Confederation of SC/ST Organisations,
Account no.- 30899921752, IFSC Code- SBIN0001639,
State Bank of India, Branch Chanderlok Building, Janpath, N. Delhi

दूरदराज से आने वाले साथियों के ठहने की व्यवस्था डॉ0 अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली पर की गयी है, अधिक जानकारी लेना चाहते हैं वे नीचे लिखे व्यक्तियों से ले सकते हैं। रेलवे आरक्षण से संबंधित कोई परेशानी हो तो भी सहायता ले सकते है।

<u>रैली से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए 09015552266 पर मिस काल करें और संदेश प्राप्त करने के पश्चात अधिक से अधिक साथियों का नाम, पता, मोबाइल और ईमेल लिखकर उसी नम्बर पर एस.एम.एस. करें।</u>

संपर्क करने के लिए अन्य आवश्यक मोबाइल नंबर –
संजय राज – 9670552211
सी.एल. मौर्य – 9013869549
सी.पी. सोनी – 9818351761
011-23354841 एवं 011-23354842

– डॉ0 उदित राज,
राष्ट्रीय चेयरमैन

भारत में छुआछूत : बहुत चौंकाने वाले हैं ये आंकड़े

हर चौथे व्यक्ति ने स्वीकार की छुआछूत की बात

आज से 64 साल पहले संविधान के द्वारा छुआछूत को खत्म कर दिया गया था लेकिन अभी भी एक चौथाई भारतीयों से ज्यादा लोग ऐसा करते हैं। अपनी तरह के सबसे बड़े सर्वे से ये बात सामने आई है।

सर्वे में जिन लोगों ने इस बात को कुबूल किया वो हर धर्म और जाति से हैं। मुस्लिम, एससी और एसटी भी इसमें शामिल हैं। सर्वे के मुताबिक छुआछूत को सबसे ज्यादा ब्राह्मण मानते हैं और यदि धर्म की बात करें तो हिंदू, सिख और जैन धर्म में भी ये फैला हुआ है।

एनसीएईआर और मैरीलैंड विश्वविद्यालय के द्वारा इस सर्वे को पूरे भारत में कराया गया है। सर्वे के दौरान 42 हजार घरों में बात की गई। एनसीएईआर की स्थापना 1956 में की गई थी और ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नॉन प्रॉफिट इकॉनामिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीव्यूट है।

इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक ये नतीजे इंडिया ह्यूमन डवलपमेंट सर्वे का हिस्सा हैं जो साल 2011-12 में किया गया था। सर्वे के पूरे नतीजे 2015 में मिल सकेंगे।

सर्वे करने वालों ने पूछा कि क्या आपका परिवार छुआछूत में विश्वास रखता है? ना में जवाब मिलने पर दूसरा प्रश्न पूछा गया कि क्या आप इस बात की इजाजत देंगे कि कोई अनूसूचित जाति का व्यक्ति आपकी रसोई में जाकर आपके बर्तनों को इस्तेमाल करे?

भारत भर में 27 प्रतिशत लोगों ने माना कि वे किसी ना किसी रूप में छुआछूत को मानते हैं और ये सबसे ज्यादा ब्राह्मणों में (52 प्रतिशत) फैली हुई है। अगड़ी जातियों में भी 24 प्रतिशत लोग छुआछूत करते हैं। ओबीसी में 33 प्रतिशत, एससी में 15 प्रतिशत और एसटी में 22 प्रतिशत लोग छुआछूत को मानते हैं।

अगर धर्म की बात की जाए तो 30 प्रतिशत हिंदू, 23 प्रतिशत सिख, 18 प्रतिशत मुस्लिम और पांच प्रतिशत ईसाई छुआछूत को मानते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं जैन (35 प्रतिशत) जो ये खुल कर मानते हैं कि वो छुआछूत में यकीन रखते हैं।

सर्वे के मुताबिक मध्यप्रदेश के 53 प्रतिशत लोग छुआछूत में भरोसा रखते हैं। हिमाचल प्रदेश में 50 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 48 प्रतिशत, राजस्थान और बिहार में 47 प्रतिशत, यूपी में 43 प्रतिशत और उत्तराखंड में 40 प्रतिशत लोग छुआछूत में यकीन रखते हैं।

पश्चिम बंगाल भारत का सबसे प्रोग्रेसिव राज्य है जहां मात्र एक प्रतिशत लोग ही छुआछूत को मानते हैं। केरल में दो प्रतिशत, महाराष्ट्र में चार प्रतिशत, नॉर्थ ईस्ट में सात प्रतिशत और आंध्र प्रदेश में 10 प्रतिशत लोग छुआछूत में यकीन करते हैं।

http://www.amarujala.com

महान गुरू गाडगे बाबा

सुरेश घोरपडे

महान गुरू डेबूजी यानि कि गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी, 1876 में महाराष्ट्र के अमरावती जिला तहसील अंजनगांव सुर्जी में शेणगांव देहात में धोबी समाज में हुआ था। धोबी समाज भारत का मुलनिवासी, नागवंशी समाज है और महान सिंधू संस्कृति नागवंशियों की थी। उनके पिता का नाम डेबूजी झिंगराजी जाणोरकर था तथा उनके माता का नाम सखुबाई था। उनके पिता के पास बहुत सारी खेती थी। लेकिन उस समय सभी बहुजन समाज में शादी तथा धार्मिक कार्यो में शराब तथा मांस का प्रयोग होता था और उस समय बकरे काटे जाते थे। उनके पिता शराब के आदी हो गए थे। उन पर गांव के जमींदार, साहूकार का बहुत कर्जा बकाया था। इस वजह से उनके घर में गरीबी आई। इसलिए उनके माता-पिता मामा के घर रहने के लिए आ गए। उनके मामा ने उन्हें संभाला।

बचपन

बचपन में गाडगे बाबा मामा के जानवर लेकर जंगल मे जाते थे। गाडगे बाबा जंगल में जाने के बाद पत्थर की सहायता से भजन गाते थे। उनके मामा के पास भी जमीन थी और उन पर भी जमींदार का कर्ज था। लेकिन गाडगे बाबा ने जमींदार का विरोध किया और खेती बचायी। गाडगे बाबा ने खेती का बहुत ध्यान रखा। उनके पत्नी का नाम कुन्ताबाई था। उन्हें आलोका और कलावती नाम की दो लड़कियां थी। उनका एक लड़का भी था। लड़की का जन्म होने के बाद बिरादरी वाले लोगों ने शराब तथा मांस खाने की दावत मांगी। लेकिन डेबूजी ने उनका विरोध किया और लोगों को बूंदी परोसी। 1 फरवरी, 1905 को गाडगे बाबा ने गृहत्याग किया। उनके बारे में प्रबोधनकार केशवरावजी ठाकरे (जो बालासाहब ठाकरे के पिताजी थे) कहते हैं कि गाडगे बाबा का गृहत्याग यानि कि कपिलवस्तू के सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने किए हुए राजत्याग की ऐतिहासिक अजर-अमर पुनरावृत्ति है।

सामाजिक परिवर्तन के लिए भारत भ्रमण

बाद में गाडगे बाबा पूरे भारत देश मे घूमे। उनके बाल बढे हुए थे। उनके कपडे फटे हुए थे। वह देहात में जाते थे। वहां पर काम करते थे। लोगों की मदद करते थे। पूरे गांव की सफाई करते थे। वे अंधश्रद्धा, जातीयता, दैववाद, गरीबी के विरोध में लोगों को प्रवचन देते थे। उनके पास पैसे नहीं रहते थे। वे दहेज के खिलाफ थे। बाबा गाडगे का मानना था कि ईश्वर पत्थर में नहीं है। वे मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को एक ही पंगत में भोजन खिलाया। एक बार अनुसूचित जाति का एक लड़का मुंबई में मजदूरी करने के लिए गया था। उसका खत उसके पिताजी के लिए आया था। उसके पिताजी अनपढ थे। वे गांव के पंडित कुलकर्णी के पास खत पढ़ाने के लिए गए। उस पंडित ने पहले लकड़ियां तोड़ने के लिए कहा। लकड़ियां तोड़े जाने के समय गुरु गाडगे बाबा वहां पर आए। उन्होंने भी लकड़ियां तोड़ने में मदद की लेकिन गांव के पंडित ने खत पढ़कर नहीं बताया। तब गाडगे बाबा ने कहा तू भी पढा नहीं, मैं भी पढा नहीं इसलिए हम शिक्षा के बिना पत्थर हैं। इसलिए उन्होंने बाद में बहुजन समाज में शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया। प्रबोधनकार केशवराव ठाकरे 'धर्म का मंदिर और मंदिरों का धर्म' किताब में कहते हैं कि मंदिरों में पूरी संपत्ति जो थी, उसे बाहर के मुल्कों के हमलावरों ने लूट लिया। इसलिए भारत देश गरीब बन गया और खेती से सोना निकालने वाला किसान भिक्षा मांगने लगा। इसलिए डॉ. पंजाब राव देशमुख ने 1930 में विधान परिषद में रखे कानून के अनुसार मंदिरों की सारी संपत्ति सरकार को कब्जे में लेना चाहिए। गाडगे बाबा अपने प्रवचन में किसी को अपने पैर नहीं छूने देते थे और कोई माला नहीं पहनते थे। पास रखे मटके को गाडगे बाबा गुरु तुकाराम महाराज की संज्ञा दिया करते थे। वे गुरु कबीर जी को बहुत मानते थे। कबीरजी कहते थे कि "जत्रा में बिठाया फतरा तिरथ बनाया पाणी, दुनिया भई दिवानी पैसे के धुलदाणी"। बाबा साहेब, तथागत गौतम बुद्ध, गुरु कबीर और महात्मा ज्योतिबा फुले को वह गुरु मानते थे। वे अशिक्षित थे। उन्होंने चमत्कार पर कभी विश्वास नहीं किया। उन्होंने सत्य नारायण पूजा का विरोध किया। वे कहते थे कि, कोई कलावती या लीलावती के साधुवाणी का जहाज समंदर मे डूब गया और सत्य नारायण की पूजा से बाहर आया। ऐसी कथा अगर सच है तो सभी महायुद्ध में इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, तथा अमरिका की बहुत सारी जहाजें युद्धों के दौरान समंदर में डूबो दी गयी। तो वो क्यों नहीं सत्य नारायण की पूजा से बाहर आ जाते ।

मानवतावादी प्रवचनकार

वे बुद्धिवादी थे। उनका प्रवचन सुनने के लिए हजारों लोग जमा होते थे। उन्होंने उस समय नासिक, पंढरपूर, पूना ऐसी जगह पर धर्मशालाएं बनायी। उन्होंने पंढरपूर की धर्मशाला डॉ. बाबा साहब आंबेडकर जी को अर्पण की। उन्होंने स्वयं के लिए कभी मंदिर या मठ बनाया नहीं। उनके माता तथा लड़कियों के निधन के बारे में बाबा गाडगे को बहुत विलंब से मालूम हुआ। उनका लड़का गाविंदा कुत्ता काटने की वजह से 1923 में गुजर गया था। उस वक्त वे रत्नागिरी जिले मे प्रवचन कर रहे थे जब उनको लडके के निधन का समाचार मिला उस वक्त उन्होने कहा की, ऐसे मर गए करोडो मै क्यो रोंवू एक के लिए। वे भविष्य कथन के खिलाफ थे। उस वक्त गांधीजी मदनमोहन मालवीय तथा शंकराचार्य कृर्त्तकोटी को भी गाडगे बाबा के कार्य के बारे मे सुनने के बाद आश्चर्य होता था। उस समय के मुंबई के मुख्यमंत्री बाळासाहब खैर इन्होने गांधीजी को गाडगे बाबा के बारे में बताया तो गांधीजी को गाडगे बाबा से मिलने की इच्छा हुई। उस वक्त वर्धा मे

पवनार आश्रम जब गाडगे बाबा आए तब हजारो लोग उन्हे देखने के लिए वहा गांधीजी को दिखाई दिए।

गाडगेबाबा और डॉ.बाबासाहब आंबेडकर :- डॉ.बाबासाहब आंबेडकर गाडगे बाबा को बहुत चाहते थे। वे गाडगे बाबा के प्रवचन में जाते थे। उस वक्त गाडगे बाबा लोगों को डॉ. बाबासाहब का तथा शिक्षा का महत्व बताते थे। डॉ.बाबासाहब 1956 मे बौध्द धम्म की दिक्षा लेने के पहले गाडगे बाबा के साथ बातचीत की थी। धर्मांतर पर चर्चा की थी। गाडगे बाबा ने पंचशिल बताया । वे मानवतावादी थे। उन्होने समता बताई। उनके कार्य की तथा त्याग की याद करना और अच्छा आचरण करना यह हमारा कर्तव्य है। वे जब बिमार थे तो उनको देखने के लिए भारत के कानूनमंत्री डॉ.बाबासाहब गए थे। गाडगे बाबा का देहांत 20 दिसंबर 1956 में हुआ। उनके समाजकार्य तथा त्याग के लिए आदरांजली!

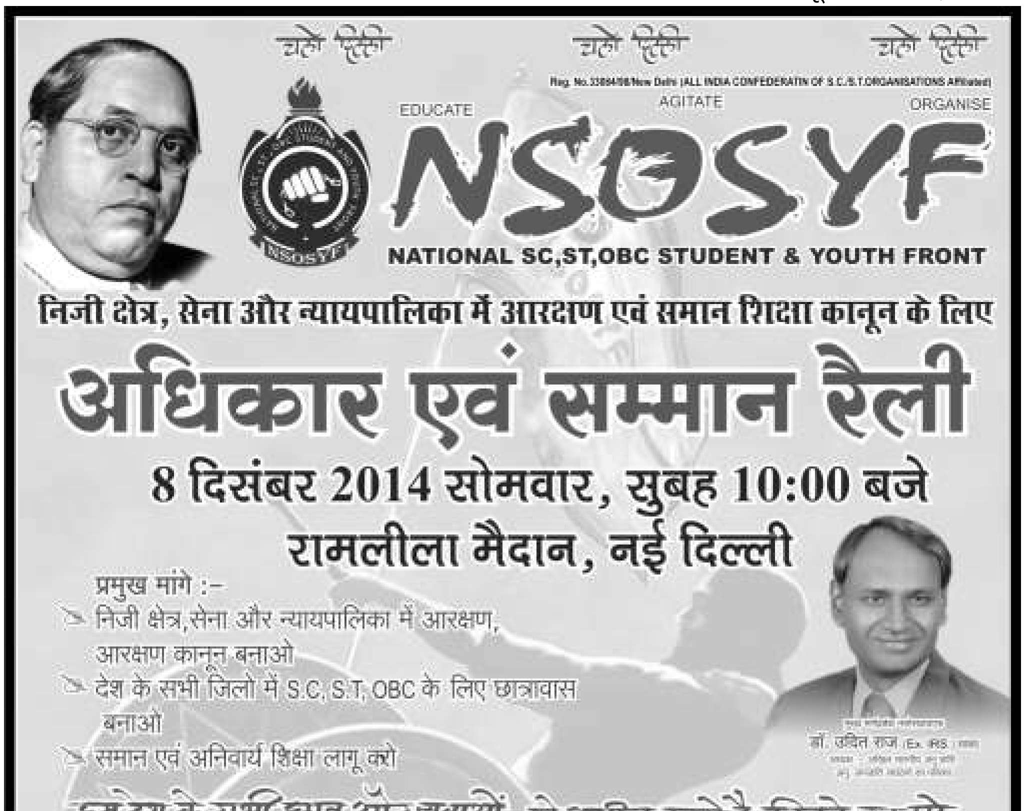

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्राफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष	:	600 रुपए
एक वर्ष	:	150 रुपए

आगामी रैली से संबंधित हैंडबिल का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि अपनी ओर से भी छपवाकर वितरित करें व तैयारी जोर शोर से करें।

अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय

परिसंघ के आवाहन पर अधिकार एवं सम्मान हेतु 17वीं महारैली

डॉ० उदित राज (पूर्व आई. आर. एस.)
राष्ट्रीय चेयरमैन

08 दिसंबर, 2014 (सोमवार) को प्रात: 10 बजे लाखों की संख्या में रामलीला मैदान, नई दिल्ली पर एकत्रित हों

प्रिय साथियों,

अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ अक्टूबर, 1997 में आरक्षण विरोधी आदेशों की वापसी के लिए अस्तित्व में आया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 30/01/1997, 02/07/1997, 22/07/1997, 13/08/1997 तथा 29/08/1997 के आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए गए थे। हमारे आंदोलन के दबाव में आकर संसद ने संविधान में 81वां, 82वां एवं 85वां संशोधन किया जिसके कारण आरक्षण बच सका।

निजीकरण एवं भूमंडलीकरण के कारण जिस तरह का विकास इस देश में हो रहा है उससे समाज दो वर्ग में बंटता जा रहा है एक है मालिक और दूसरा श्रमिक। जिनका उत्पादन शक्तियों पर कब्जा नहीं है, वे इस दौर में मजदूर के अलावा और कुछ नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है कि दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों के हाथ में उत्पादन शक्तियों पर कोई मालिकाना हक नहीं है। गत् कई वर्षो से अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करता आ रहा है लेकिन यूपीए की सरकार ने समितियां तो तीन-तीन बनायी लेकिन देश की पूंजीपति संगठनों ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी के नाम पर मामले को रफा-दफा करके इस अधिकार से वंचित रखा है। इस अधिकार का न मिलने का दूसरा कारण यह रहा कि अनुसूचित जाति और जन जाति के हजारों संगठन और नेता गलतफहमी में या इरादतन समाज के संसाधनों का दुरूपयोग करते रहे हैं और कहते हैं कि लड़ाई समाज की है लेकिन वास्तव में वह अपने संगठन को बचाने के लिए शक्ति का उपयोग करते रहे हैं। संगठन बचेगा तभी उनकी नेतागिरी जिंदा रहेगी। दलित समाज के भोले-भाले लोग इसे मिशन समझ लिये लेकिन परिसंघ ने कभी संगठन बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी क्योंकि वह आंदोलन के रूप में ढ़ल गया था और पूरी ताकत से अधिकार के लिए संघर्ष किया लेकिन समाज का सहयोग नहीं मिल सका इसलिए अभी तक ये उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए। परिसंघ गैर राजनीतिक संगठन है और इसके मंच पर साल में एक बार दिल्ली में इकट्ठा होने की ही अपील होती रही है। परिसंघ के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वे तो पूर्णकालिक रूप से लगे रहते ही हैं। समाज से अपील है कि राजनीतिक एवं अपने सामाजिक संगठनों से ऊपर उठकर अधिकार प्राप्ति के लिए वर्ष में एक दिन का समय दे दें तो भी हम लड़ाई जीत जाएंगे। क्या एक दिन का समय और एक दिन का वेतन मांगना बहुत ज्यादा है ? लोग केवल एक दिन लाखों की संख्या में दिल्ली में आकर खड़े हो जाएं तो भी राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बन जाएगा तो हमारी मांगे जैसे : आरक्षण कानून बनवाना, पदोन्नति में आरक्षण का विधेयक संसद में पास कराना, अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989, को मजबूत करने के लिए संसद में लंबित बिल, स्पेशल कंपोनेंट प्लान एवं ट्राइबल सब प्लान को आबादी के अनुपात में बजट आवंटन को कानूनी मान्यता, एक राज्य में बना जाति प्रमाण पत्र दूसरे राज्य में मान्य होना, सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति, समयबद्ध पदोन्नति, संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति, समान शिक्षा एवं सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों की मान्यता जैसे अधिकारों को पूरा कराना बिल्कुल संभव हो जाएगा।

यक्ष प्रश्न यह है कि परिसंघ के ही बैनर के नीचे लोग क्यों जमा हों ? जवाब है कि 1997 से लेकर अब तक किसी संगठन ने एक अधिकार भी समाज को नहीं दिलाया है। जिस दिन परिसंघ नकारा हो जाए, समर्थन मत देना। संवैधानिक संशोधन तो करवाया ही उसके बाद जितने भी अधिकार जोड़े गए चाहे निजी क्षेत्र में आरक्षण को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाना और जातिविहीन समाज की स्थापना के लिए 2001 में एक विशाल दीक्षा, 2006 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण में पैरवी करना, अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम को कमजोर करने का यूपी सरकार के प्रयास को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बचाना, पिछड़ों के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू कराने की लड़ाई लड़ना, लोकपाल में आरक्षण, आदि। क्या कोई और संगठन इतने अधिकार दिलवा पाया ?

डॉ. उदित राज दलितों-आदिवासियों की आवाज उठाने संसद में भाजपा की ओर से गए हैं और इसके लिए भाजपा का धन्यवाद। हमें इस बात का गर्व है कि डॉ. उदित राज के आवाहन पर भागीदारी के लिए लोक सभा के चुनाव में दलितों ने भाजपा को सर्वाधिक वोट दिया। सरकार आते ही सकारात्मक कार्य शुरू हुआ। जो अधिकार जन प्रतिनिधि के द्वारा दिए जाते थे, न्यायपालिका उसे छीनने का कोशिश करती थी लेकिन सरकार ने 121वीं संवैधानिक संशोधन करके राष्ट्रीय न्यायायिक नियुक्ति आयोग जिसमें 6 सदस्य होंगे। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस या किसी भी जनतांत्रिक देश में जज की भूमिका जज बनाने में नहीं होती लेकिन भारत में ही ऐसा क्यूं ? यह कार्य दस साल में यूपीए सरकार नहीं कर सकी और मोदी जी के सरकार आते ही अच्छे दिन लाने लगी। इसके अतिरिक्त पार्टी ने उदित राज को संसद में सवाल उठाने का मौका दिया जो अभी तक नहीं उठा। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के अनुदान बजट पर संसद में कभी चर्चा नहीं हुयी थी और इस पर बहस डॉ. उदित राज से शुरू हुयी और उन्होंने कहा कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत जितना पैसा अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए वह कभी नहीं मिला। पिछली सरकारों ने ऐसी विरासत छोड़ी कि यह आवंटन कभी 8 प्रतिशत से ज्यादा रहा ही नहीं। 2014-15 के प्लान बजट के तहत कुल 5,75,000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस बार भी दलितों के लिए 8.79 प्रतिशत का ही प्रावधान है। यदि अनुसूचित जाति की आबादी 15 प्रतिशत व जन जाति की 7.5 प्रतिशत भी मान ली जाए तो अनुसूचित जाति के लिए 86,250 करोड़ रूपए होना चाहिए था जबकि बजट में 50,548 करोड़ रूपए का ही प्रावधान है। इसी प्रकार अनुसूचित जन जाति के लिए 43,125 करोड़ रूपए का प्रावधान होना चाहिए था जबकि 32, 387 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। अगर हम लाखों की संख्या में इकट्ठा हों तो डॉ. उदित राज को और ताकत मिलेंगी और हमारी मांगें पूरी होगी।

फूले-शाहू या सामाजिक न्याय की विचारधारा मानने वाले से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं हो सकता और यह परिसंघ का अटूट विश्वास है। जब भारत की शासन सत्ता में दलित, आदिवासी एवं पिछड़े नहीं थे तो देश बाहर वालों का गुलाम था और आजादी के बाद सबकी भागीदारी हुयी है चाहे कम हो या ज्यादा, तो क्या किसी की हिम्मत है कि सोच भी सके कि वह भारत को गुलाम बना लेगा ? हम तो किसी भी दृष्टि से जातिवादी नहीं है लेकिन जो वंचित हैं उनके लिए अधिकार मांग करके एक खुशहाल एवं समतामूलक समाज, एकात्म समाज, एक मजबूत राष्ट्र बनाने के अलावा और हमारा क्या उद्देश्य हो सकता है ?

भले ही जो लोग डॉ. उदित राज या परिसंघ को न भी मानते हों तो भी समाज के हित के लिए इस अधिकार एवं सम्मान प्राप्ति महा अभियान में 8 दिसंबर, 2014 को रामलीला मैदान, अजमेरी गेट, नई दिल्ली में लाखों की संख्या में प्रातः 10 बजे शामिल हों।

बी. एल. बैरवा, अध्यक्ष, एससी/एसटी रेलवे एम्प. एसो. | **निवेदक** | अशोक कुमार, महासचिव, एससी/एसटी रेलवे एम्प. एसो.

भवननाथ पासवान, जगजीवन प्रसाद, डॉ0 अनिल कुमार, एस. पी. सिंह, धर्म सिंह, बलवंत सिंह चार्वाक (उ0प्र0), इंदिरा आठवले, सिद्धार्थ भोजने, प्रकाश पाटिल (महाराष्ट्र), एस. पी. जरावता, महासिंह भूरानिया, मनीराम सरोहा (हरियाणा), तरसेम सिंह, हंसराज हंस, दर्शन सिंह चंदेढ़ (पंजाब), विनोद कुमार (मो.- 9871237186), नेतराम ठगेला, कंवर सिंह, डॉ. नाहर सिंह, एन. डी. राम, रविंद्र सिंह, ब्रह्म प्रकाश, डॉ. धनंजय, डॉ. अंजू काजल, ए. के. लाल, जे. आर. हरनौटिया (दिल्ली), मूला राम, इन्द्राज सिंह, विश्राम मीना (राजस्थान), हीरा लाल, एच.सी. आर्या, रोहित कुमार, जयपाल सिंह (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहरा (उड़ीसा), परम हंस प्रसाद, बी. भारती, आर. बी. सिंह, पी. के. राय (म.प्र.), रामू भाई वघेला, आर. एस. मौर्या, एन. जे. परमार (गुजरात), एस. करुपैय्या, एम. पी. कुमार, जी. श्रीनिवासन (तमिलनाडु), के. रमनकुट्टी (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), महेश्वर राज, जी. शंकर, आई मैसया, एस. रामकृष्णा, जे. बी. राजू, वाई. एम. विजय कुमार, बी. नरसिंह राव, पी. वी. रमणा (आन्ध्र प्रदेश), अनिल मेश्राम, हर्ष मेश्राम (छत्तीसगढ़), कमल कृष्ण मंडल, रामेश्वर राम, सपन हलदर (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, दिनेश कुमार, दामोदर बौद्ध (झारखण्ड), आर. के. कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदन राम, कुमार धीरेंद्र (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, जी. वेंकटस्वामी, पुरुषोत्तम दास (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.)

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ

पत्राचार : टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-1, फोन : 23354841-42, टेलीफैक्स : 23354843 Email : dr.uditraj@gmail.com

जय भीम ! जय भारत !!

अनुसूचित जाति / जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय

परिसंघ

के आवाहन पर

अधिकार एवं सम्मान

डॉ० उदित राज (पूर्व आई. आर. एस.)
राष्ट्रीय चेयरमैन

17वीं महारैली

08 दिसंबर, 2014 (सोमवार) को प्रात: 10 बजे
रामलीला मैदान, नई दिल्ली पर

मुख्य मांगें

1. पदोन्नति में आरक्षण के लिए 117वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पास करवाना 2. निजी क्षेत्र एवं न्यायपालिका में आरक्षण 3. सफाई काम में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना 4. खाली पदों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान 5. समान शिक्षा 6. भूमिहीनों को भूमि 7. आरक्षण कानून बनाओ 8. अनुसूचित जाति योजना एवं जन जाति उप योजना कानून बनाओ 9. एक राज्य का जाति प्रमाण-पत्र सभी राज्यों में मान्य हो 10. महंगाई की दर से छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी

बी. एल. बैरवा, अध्यक्ष, एससी/एसटी रेलवे एम्प. एसो. निवेदक : **अशोक कुमार, महासचिव, एससी/एसटी रेलवे एम्प. एसो.**

भवननाथ पासवान, जगजीवन प्रसाद, डॉ0 अनिल कुमार, एस. पी. सिंह, धर्म सिंह, बलवंत सिंह चार्वाक (उ0प्र0), इंदिरा आठवले, सिद्धार्थ भोजने, प्रकाश पाटिल (महाराष्ट्र), एस. पी. जरावता, महासिंह भूरानिया, मनीराम सरोहा (हरियाणा), तरसेम सिंह, हंसराज हंस, दर्शन सिंह चंदेढ़ (पंजाब), विनोद कुमार (मो.– 9871237186), नेतराम ठगेला, कंवर सिंह, डॉ. नाहर सिंह, एन. डी. राम, रविंद्र सिंह, ब्रह्म प्रकाश, डॉ. धनंजय, डॉ. अंजू काजल, ए. के. लाल, जे. आर. हरनौटिया दिल्ली), मूला राम, इन्द्राज सिंह, विश्राम मीना (राजस्थान), हीरा लाल, एच.सी. आर्या, रोहित कुमार, जयपाल सिंह (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहरा (उड़ीसा), परम हंस प्रसाद, बी. भारती, आर. बी. सिंह, पी. के. राय (म.प्र.), रामू भाई वघेला, आर. एस. मौर्या, एन. जे. परमार (गुजरात), एस. करुपैय्या, एम. पी. कुमार, जी. श्रीनिनवासन (तमिलनाडु), के. रमनकुट्टी (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), महेश्वर राज, जी. शंकर, आई मैसया, एस. रामकृष्णा, जे. बी. राजू, वाई. एम. विजय कुमार, बी. नरसिंह राव, पी. वी. रमणा (आन्ध्र प्रदेश), अनिल मेश्राम, हर्ष मेश्राम (छत्तीसगढ़), कमल कृष्ण मंडल, रामेश्वर राम, सपन हलदर (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, दिनेश कुमार, दामोदर बौद्ध (झारखण्ड), आर. के. कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदन राम, कुमार धीरेंद्र (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, जी. वेंकटस्वामी, पुरुषोत्तम दास (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.)

पत्राचार : टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–1, फोन : 23354841–42, टेलीफैक्स : 23354843

Email : dr.uditraj@gmail.com www.uditraj.com

Haryana Government urged to continue reservation in promotion-Udit Raj

New Delhi, 18 Nov, 2014: Today a large number of SC/ST employees and officers under the leadership of Shri Sat Prakash Jrawta met Dr. Udit Raj, Chairman, All India Confederation of SC/ST Organizations, at his residence, T-22 Atul Grove Road, Tolstoy Marg, New Delhi.

The delegation ventilated its grievance that due to the complacency on the part of previous State Government in Haryana, headed by Shri Bhupinder Singh Hooda, this crisis of reservation in promotions has cropped up. The Haryana Government implemented 85th Amendment from 16th March 2006 and it was challenged in Punjab & Haryana High Court, Chandigarh in 2011 (CWP 17280). The High Court delivered the judgment in August 2012, asking the Government to follow the conditions laid down by the Supreme Court judgment of Nagraj, 2006. The State Government constituted a Committee headed by P. Raghvendra, an IAS Officer of Haryana in February 2013. The Committee gave its findings in favour of reservation in promotion, i.e. to implement Nagraj judgment. The mischief was done by the Government not to place the findings of this Committee before the High Court and as a result, the adverse judgment was delivered on 14th November, 2014, quashing the 2006 and 2013 orders of State Government. Dr. Udit Raj urged the Chief Minister of Haryana State to continue reservation in promotions and meanwhile all necessary remedial measures should be explored. The judgment dated 14th November 2014 has come in absence of proper argument and facts. If previous Government would have placed the findings of Raghvendra Committee before the Hon'ble High Court, this judgment would not have come. If Punjab & Haryana High court has invalidated reservation in promotion contrary to 2006 orders and interim order dated 7th August, 2012, it is because of poor representation by the Government of Haryana. The judgment is very clear which says that reservation in promotion will continue but with conditions that if there is inadequacy in representation, backwardness and in conformity with efficiency of administration. Dr. Udit Raj further informed that the matter will be taken up at the level of National President of B.J.P. Shri Amit Shah. The Central Government will be persuaded in the coming session of Parliament to pass the Bill to give reservation in promotions which was already introduced in previous Lok Sabha. Dr. Udit Raj appealed to the leaders of employees and officers of Haryana that they should have faith in Government and their interests will be guarded at all levels.

Muslims, dalits and tribals make up 53% of all prisoners

Subodh Varma

NEW DELHI: Muslims, dalits and adivasis — three of the most vulnerable sections of Indian society — make up more than half of India's prison population, according to an official report on prisons released this month. Although the proportion of these three communities in India adds up to about 39%, their share amongst prisoners is considerably higher at 53%.

India had 4.2 lakh people in prison in 2013. Nearly 20% of them were Muslims although the share of Muslims in India's population is about 13% according to Census 2001. Religion-wise data from Census 2011 is yet to be released but it is unlikely to be much different. Dalits make up 22% of prisoners, almost one in four. Their proportion in population is about 17% according to Census 2011. While adivasis make up 11% of prisoners, their share in the general population is 9%.

Most experts say that this disturbing trend is not because these communities commit more crimes. Rather, it arises because they are economically and socially under-privileged, unable to fight costly cases or often even pay for bail. Some say that these communities are targeted with false cases.

Former chief justice of Delhi high court Rajinder Sachar, who headed the committee that brought out a report on the condition of Muslim community in India in 2006, pointed out that there had been several cases of Muslim youths being acquitted after years in prison.

"Poverty is more prevalent among these three communities and that becomes an obstacle in dealing with the legal system," said Colin Gonsalves, human rights activist and lawyer.

"Our system has an ingrained communal and casteist bias. Also, the proportion of these communities in the police officers and even judiciary is less. These are key factors behind this shocking imbalance," he added.

Pointing out that nearly 68% of the prisoners are undertrials, Abusaleh Sharif, who was member-secretary of the Sachar Committee and later brought out an updated report on the conditions of Muslims, said that they had to remain behind bars because of inability to negotiate the hostile system.

"Among those in prison under preventive detention laws, nearly half are Muslims. This is the kind of thing that the government needs to speedily investigate and resolve," Sharif said.

Ramesh Nathan of the National Dalit Movement for Justice alleged that false cases are filed against dalits in order to intimidate them, causing this disturbingly high number of prisoners among vulnerable sections.

"In my experience as a lawyer, whenever a dalit person files a case under the Atrocities Act, a false countercase under some penal code provision is filed by the culprits," he said.

Prison statistics are published annually by the National Crime Records Bureau since 1995, although caste breakup is available since 1999. The proportions of Muslims, dalits and adivasis have remained virtually unchanged over the past 15 years indicating that this is a systemic problem.

(Courtesy- Times of India)

Jai Bheem !

Jai Bharat !!

All India Confederation of SC/ST Organisations

Dr. Udit Raj (Ex. I. R. S.)
National Chairman

Call

For Dignity & Rights

17th MAHARALLY

at

Ramlila Maidan, New Delhi
on 08th Dec., 2014 (Monday) at 10 AM

DEMANDS

1. Pass 117th Constitutional Amendment to provide Reservation in Promotion 2. Reservation in Private Sector and Judiciary 3. Ban contract system in Safai Work 4. Fill up backlog posts by special drive 5. Right to Equal Education 6. Land to the Landless 7. Enact Reservation Act 8. Legislation of SCP & TSP 9. Caste certificate of one State should be valid in other States 10. Raise scholarship amount as per price index.

By

B. L. Bairwa, President, AISCTREA

Ashok Kumar, Gen. Secy., AISCTREA

Bhawan Nath Paswan, Jagjivan Prasad, Dr. Anil Kumar, S. P Singh, Dharm Singh, Balwant Singh Charwak (UP), Indira Athawale, Siddharth Bhojne, Prakash Patil (M.S.), S.P. Jaravta, Maha Singh Bhurania, Maniram Saroha (Haryana), Tarsem Singh, Hansraj Hans, Darshan Singh Chanded (Punjab), Vinod Kumar (M.-9871237186), Netram Thagela, Kanwar Singh, Dr. Nahar Singh, N. D. Ram, Ravinder Singh, Brahm Prakash, Dr. Dhananjay, Dr. Anju Kajal, A. K. Lal, J. R. Harnautiya (Delhi), Moola Ram, Indraj Singh, Vishram Meena (Rajasthan), Hira Lal, H.C. Arya, Rohit Kumar, Jaipal Singh (U.K.), Aalekh Malik, D. K. Behera (Orissa), Param Hans Prasad, B. Bharti, R. B. Singh, P. K. Roy (M.P.), Ramu Bhai Vaghela, R.S. Maurya, N. J. Parmar (Gujarat), S. Karuppaiah, M. P. Kumar, G. Sriniwasan (T.N.), K. Raman Kutty (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), Maheshwar Raj, G. Shankar, I Mysaiah, S. Ramkrishna, J. B. Raju, Y. M. Vijay Kumar, B. Narsingh Rao, P. V. Ramna (A.P.), Anil Meshram, Harsh Meshram (Chattisgarh), Kamal Krishna Mandal, Rameshwar Ram, Sapan Haldar (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Dinesh Kumar, Damodar Baudh (Jharkhand), R. K. Kalsotra (J&K), Madan Ram, Kumar Dhirendra (Bihar), J. Shriniwaslu, G. Venkatswamy, Purushottam Das (Karnataka), Seetaram Bansal (H.P.).

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1, Tel : 23354841-42
Email : dr.uditraj@gmail.com www.uditraj.com

Sample of the Handbill for the forthcomming Rally is being published. It is an earnest appeal to the Confederation Leaders that they should get it printed and distributed

Confederation Call For 17th Rally For Dignity & Rights

Dr. Udit Raj (Ex. I. R. S.)
National Chairman

On 08th December, 2014 (Monday) at 10 AM, Lakhs of People to Assemble at Ramlila Maidan, New Delhi.

18/10/2014

Dear friends,

All India Confederation of SC/ST Organizations came into being in October 1997 to cancel anti-reservation orders dated 30/01/1997, 02/07/1997, 22/07/1997, 13/08/1997 and 29/08/1997 issued by the Department of Personnel & Training, Government of India. Due to our vibrant struggle, the Government made 81st, 82nd and 85th amendments in the Constitution of India and the reservations were protected.

Privatization and globalization have divided the world in two classes – the rich and the poor. Those who do not own means of production will be reduced to labourers. It is very much evident that the Dalits and Adivasis do not own means of production. For the past many years the All India Confederation has been demanding reservation in private sectors but the UPA Government got away with the excuse of making three committees which yielded nothing except an eye-wash under the pretext of 'corporate social responsibility'. Lack of consciousness and existence of multiple organizations came in the way of unity to muster enough support to build the pressure on the Government. These organizations, deliberately or innocently, have been misusing the resources, time and talent under the notion that they are carrying forward the caravan of Baba Saheb Dr. Ambedkar. In fact, most of them have exhausted their energy in protecting their own organization rather than pressurizing the Government to accede to their demands. Why did they waste their energy to protect their own organization, had their vested interests to save their own leadership as office-bearers not been there? So all their efforts were finished before reaching the target and in such a situation, they sometimes harmed the society more than whatever little they could serve it. The innocent Dalits mistook it as a mission and the Confederation never passed through such phase because it got culminated into a nationwide movement just after its making under the visionary leadership of Dr. Udit Raj. Under these circumstances, our goals are still unachieved. We would like to clarify once again that our Confederation is non-aligned to any political party and we appeal to all concerned to come to Delhi to join us on 8th of December 2014 at 10 a.m. at Ram Lila Maidan, Delhi Gate. All are requested to join their hands with us and we are sure to win. One day's time or one day's salary is not a big demand for such a big cause. If lakhs of people come to Delhi to render their support, it will have a great bearing on the Government and the demands like reservation in promotions, redressal of SC/ST grievances, passing of Bill to strengthen the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989, allocation of budget under Special Component Plan and Tribal Sub Plan as per population ratio, recognition of caste certificate of one State in other State, ban on contract system in Safai work and regularizing them and their time-bound promotion, equal education for all and recognition to SC/ST organizations by Government departments. All these rights would become a reality if we all fight unitedly.

The main question arises as to why we should all unite under the banner of Confederation. The answer is that since 1997 not any other organization has achieved even a single right. If we become like any other organization that do nothing, we will not ask for any support and will end up all activities. We have already fought relentlessly for reservation in private sectors, reservation in promotions in the Supreme Court of India in 2006, successfully defended the dilution of SC/ST Atrocities Act by the UP Government in Allahabad High Court, reservation in higher education for OBCs, reservation in Lok Pal, etc., etc. Did any other organization fight for and achieve so many rights for SC/STs and OBCs?

Dr. Udit Raj has reached to the Parliament to raise the voice of weaker section. We thank you and the BJP for this. It was on the call given by Dr. Udit Raj that SC/STs supported BJP in a big way in Lok Sabha elections. The BJP Government has started good beginning by making 21st Constitutional Amendment to make National Judicial Appointments Commission. What is happening is that the rights which we get from people's representatives are being diluted by judiciary. Now the judges will be selected by the Commission comprising six members and one of them will be from SC/ST/OBC. Now there is a chance to get the fairer deal. In no advanced countries like America, England, Germany, Russia or any democratic nation, the judiciary has role to play in their own appointments. Why this practice in India? The UPA Government could not do this job in ten years but the Modi ji made it possible to bring 'good days'. Besides, the party gave the opportunity to Dr. Udit Raj to raise the issues in the Parliament. There had never been any discussion in the Parliament on the Ministry of Social Justice & Empowerment while passing the demand for grant since Independent. Dr. Udit Raj raised the issue of budget allocation for SCs/STs according to their population. In the budget Rs. 50,548 crore is allocated but it should have been Rs. 86,250 crore. For STs the allocation was Rs. 32,387 crore whereas as per Tribal Sub Plan it should be Rs. 43,125 crore. This exploitative policy was pursued by the former Governments. If we could muster support in lakhs under the leadership of Dr. Udit Raj, we will certainly gain dignity and right which other members of Parliament could not do.

The Confederation believes that we are true nationalist and our efforts automatically culminate in strengthening the unity and integrity of India. Thus, believers in social justice are the purest nationalists. Please do not forget the fact that India spent hundreds of years in slavery and insubordination of the foreigners when there was no participation of different communities and castes in the governance of the country. The SCs/STs and OBCs got an opportunity to participate in the governance of the country after Independence and nobody can now think of colonizing it. We are not casteists from any angle. But we are fighting for the rights of the people who are deprived of their rights for centuries. Our main aim is to build a society which can achieve a strong and happy nation. Even those who do not accept the leadership of Dr. Udit Raj and are the part of the Confederation, they should also participate in large numbers for the cause. The cause is supreme. Please join the Rally in lakhs at Ramlila Maidan, Delhi Gate at 10 a.m. on 8th December, 2014.

B. L. Bairwa, President, AISCTREA **By** **Ashok Kumar, Gen, Secy., AISCTREA**

Bhawan Nath Paswan, Jagjivan Prasad, Dr. Anil Kumar, S.P Singh, Dharm Singh, Balwant Singh Charwak (UP), Indira Athawale, Siddharth Bhojne, Prakash Patil (M.S.), S.P. Jaravta, Maha Singh Bhurania, Maniram Saroha (Haryana), Tarsem Singh, Hansraj Hans, Darshan Singh Chanded (Punjab), Vinod Kumar (M.- 9871237186), Netram Thagela, Kanwar Sen, Dr. Nahar Singh, N. D. Ram, Ravinder Singh, Brahm Prakash, Dr. Dhananjay, Dr. Anju Kajal, A. K. Lal, J. R. Harnautiya (Delhi), Moola Ram, Indraj Singh, Vishram Meena (Rajasthan), Hira Lal, H.C. Arya, Rohit Kumar, Jaipal Singh (U.K.), Aalekh Malik, D. K. Behera (Orissa), Param Hans Prasad, B. Bharti, R. B. Singh, P. K. Roy (M.P.), Ramu Bhai Vaghela, R.S. Maurya, N. J. Parmar (Gujarat), S. Karuppaiah, M. P. Kumar, G. Srinivasan (T.N.), K. Raman Kutty (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), Maheshwar Raj, G. Shankar, I Mysaiah, S. Ramkrishna, J. B. Raju, Y. M. Vijay Kumar, B. Narsingh Rao, P. V. Ramna (A.P.), Anil Meshram, Harsh Meshram (Chattisgarh), Kamal Krishna Mandal, Rameshwar Ram, Sapan Haldar (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Dinesh Kumar, Damodar Baudh (Jharkhand), R.K. Kalsotra (J&K), Madan Ram, Kumar Dhirendra (Bihar), J. Shriniwaslu, G. Venkatswamy, Purushottam Das (Karnataka), Seetaram Bansal (H.P.).

All India Confederation of SC/ST Organisations

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1, Tel : 23354841-42, Telefax: 23354843, Email : dr.uditraj@gmail.com

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 18 ● Issue 1 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 16 to 30 November, 2014

Important Instruction for the Rally to be held on 8th December at Ramlila Ground, New Delhi

Friends,

You must have come to know that on 8th December, 2014 once again a Maha-Rally will be held at Ram Lila Maidan, New Delhi at 10 AM onwards. We intend to surpass the magnitude of the 11th December, 2000 Rally. Numbers do count, which we have proved earlier also. This is the 17th Rally of its kind. Everybody knows that All India Confederation of SC/ST Organizations is a non-political entity and will remain as such forever. This is the biggest country-wide Organization of our Samaj and we are bent upon making it more forceful. Due to jealousy or due to ignorance some people are asking how a Member of Parliament from the ruling party can hold such a Rally. We reply that it is not the first time that such a Rally is being held but it is the 17th Rally of its kind. Second, Dr. Udit Raj is holding this Rally not as a Member of Parliament but in his capacity as the National Chairman of the All India Confederation of SC/ST Organizations. We know the present Government should be given some time to work out deliver the result. If we break up the sequence of our Rallies, our rank and file will get disillusioned and divided. As a result, the bogus Dalit leaders may benefit from this position. A mother, who loves his child the most, does not give milk unless the child weeps. Only with this object in view we are gathering together on this occasion so that the Government may feel our pulse and power. Only the Karamcharis and Adhikaris are our real strength and in the last Lok Sabha we got astonishing results. If we have supported the Government, we do expect them to respect our dignity. The Prime Minister had said during the election campaign that the coming decade will be the decade of the Dalits, the Adivasis and the downtrodden, and we are dead sure, the work which the previous Government could not do during their entire lifespan, will be done by the present Government.

Friends, this is the time to show our collected power. The National President of BJP, Shri Amit Shah, senior leader Shri Nitin Gadkari and others have consented to address the Rally. We will try to invite the Hon'ble Prime Minister too to address the Rally if his time permits him. We are not disclosing who we have been invited to address the Rally since it would give an impression as if some people would attend the Rally not because of Confederation but because of the presence of senior political leaders and top govt. functionary. In fact, your strength will only make the ground for the Rally and if the Rally weakens in their presence, it would have an adverse impact on our movement. Therefore, unite with all forces at your command to make the Rally a grand success. Photocopy of the Railway order is on the reverse of this handbill. Railway has issued separate orders in this respect. You may seek their help for participation in the Rally. Holding such a big Rally without money is not at all possible. Therefore, deposit the money in the account of the Confederation as soon as possible. You may think if the Rally fails in the presence of such senior leaders who make policy decisions of the Government, what impact it would leave on our movement. Therefore, participate in the Rally by contacting them. Inform the Confederation via sms or e-mail about your financial contribution made for the Rally. Account details follow:

All India Confederation of SC/ST Organisations,
Account no. 30899921752, IFSC Code SBIN0001639,
State Bank of India, Branch Chandralok Building, Janpath, New Delhi-1.

Arrangements for the night stay have been made at Dr. Ambedkar Bhawan, Rani Jhansi Road, Karol Bagh, New Delhi for the participants coming from far flung places. More information may be had from Shri Sanjay Raj, Mobile: 9670552211; Shri C.L. Maurya, Mobile: 9013869549; Shri C.P. Soni, Mobile: 9818351761, including any difficulty faced in railway reservation.

To know more about the Rally, please give a miss-call at 09015552266 and on receipt of the message, please send more and more names of your friends and colleagues, their address, mobile and e-mail number on the same number.

- Dr. Udit Raj,
National Chairman

Awareness Camp at Paloura-Jammu to Save Reservation

R. K. Kalsotra

Jammu, 22 Nov 2014: Shri Guru Ravi Dass Sabha organized an Awareness Camp to Save Reservation at the **Ravi Dass Temple** where Shri R.K. Kalsotra, State President, All India Confederation of SC/ST/OBC Organizations was invited along with Shri M.R. Bangotra, Retd. CEO and Dr. Raj Paul Hans, Retd Director of J&K Government. President of the Sabha welcomed the guests and apprised the participants about the key role of Shri R.K. Kalsotra and the All India Confederation to save Reservation and its implementation, especially issuance of **SRO-537** according to which one step higher Reservation was started in J&K for which they had struggled with Mr. Kalsotra. Shri R.K. Kalsotra apprised the participants about holding of a big **Save Reservation Maharally at Delhi on 8th December 2014** with a view to pressurize the Government of India to pass **Reservation Act** to make reservations in private sector mandatory and Reservation in promotions and adequate funding for SC/ST/OBC component plan. Shri Kalsotra appealed to the participants to mobilize the masses for participation in the Maharally in large numbers. Shri M.R. Bangotra cautioned the intellectuals of the community that if they do not come forward, Reservation Rights would not come on their own. He requested them to join their hands with the All India Confederation for the noble cause. Shri Om Parkash, Retd employee, said that in J&K there is no Reservation for

ad hoc and temporary posts and the Government regularizes them at a later date and only the All India Confederation is fighting for reservation in ad hoc and temporary posts. They have also gheraod the J&K State Assembly on this issue but to no avail. So it is our moral duty to support the All India Confederation for the genuine cause for the sake of our future generations. Others who spokes on the occasion included S/Shri Rattan Lal Hans, Dev Raj Hans, Sham Lal and Gaurav. At the end, the President of the Sabha assured Shri Kalsotra that members of their Sabha will participate in the Maharally at Delhi's Ram Lila Ground on 8th December 2014, in large numbers, for which they will call another big meeting of the Sabha to finalize the participants' lists and thanked all the members for their participation in the meeting.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com
Computer typesetting by N. K. Karn